किरण सिंह और अन्य

बनाम

चमन पी. आसवान और अन्य।

[मुखर्जिया, विवियन बोस, गुलाम हसन और वेंकटरामा अय्यर जेजे.]

वाद मूल्यांकन अधिनियम (VII/1887), धारा 11-कम मूल्यवान अपील और निम्नतर अधिकारिता वाले न्यायालय में प्रस्तुत की गई अपील-क्या गुण-दोष पर उसके द्वारा पारित डिक्री एक शून्य है-चाहे गुण-दोष पर निर्णय में केवल रूप का परिवर्तन हो या त्रुटि, वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 के अर्थ में पूर्वाग्रह-क्या कोई पक्ष जो न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करता है, अति-मूल्यांकन या कम-मूल्यांकन के आधार पर पूर्वाग्रह की शिकायत कर सकता है।

वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 के साथ-साथ सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 और 99 की अंतर्निहित नीति यह है कि जब किसी मामले की सुनवाई किसी न्यायालय द्वारा गुण-दोष और दिए गए निर्णय के आधार पर की जाती है, तो इसे विशुद्ध रूप से तकनीकी

आधार पर नहीं उलट दिया जाना चाहिए, जब तक कि न्याय की विफलता न हो। विधायिका की नीति क्षेत्रीय और आर्थिक दोनों क्षेत्राधिकार के बारे में आपत्तियों को तकनीकी के रूप में मानने की रही है और जब तक कि गुण-दोष पर पूर्वाग्रह न हो, तब तक अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार के लिए तैयार नहीं है।

केवल रूप का परिवर्तन वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 के अर्थ के भीतर पूर्वाग्रह नहीं है और न ही मामले के गुण-दोष पर निर्णय में केवल त्रुटि है। यह सीधे तौर पर अति-मूल्यांकन या कम-मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।

पूर्वाग्रह रहा है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्धारित किया जाना है। धारा 11 के तहत अधिकारिता का प्रयोग एक न्यायसंगत है, जब किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अति-मूल्यांकन या कम-मूल्यांकन और न्याय की परिणामी विफलता के परिणामस्वरूप अधिकारिता की गलत धारणा की गई हो। इस तरह के अधिकार क्षेत्र को बारीकी से परिभाषित करना या इसे घोषित सीमाओं के भीतर सीमित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है।

एक पक्ष जिसने अपने स्वयं के मूल्यांकन पर अपनी पसंद के मंच का सहारा लिया है, उसे स्वयं किसी भी पूर्वाग्रह की शिकायत करते हुए नहीं सुना जा सकता है।

रामदेव सिंह बनाम राज नारायण (आई. एल. आर. 27 पटना 109); राजलक्ष्मी दासी बनाम कात्यायनी दासी (आई. एल. आर. 38 कल. 639); सिदप्पा वेंकटराव बनाम रचप्पा सुबराव (आई. एल. आर. 36 बोम. 628); रचप्पा सुब्राव जाधव बनाम सिदप्पा वेंकटराव जाधव (46 आई. ए. 24); केलु अच्चन बनाम चेरिया पार्वती नेथियार (जे. एल. आर. 46 मैड. 631); मूलचंद बनाम राम किशन (आई. एल. आर. ऑल 55) को संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 14/1953

उच्चतम न्यायालय द्वारा 29 अक्टूबर, 1951 के अपने आदेश द्वारा पटना में उच्च न्यायालय (सिन्हा और राय जेजे.) के 19 जुलाई, 1950 के निर्णय और डिक्री से 1946 के अपीलीय डिक्री संख्या 1152 से 24 मई, 1946 के निर्णय और डिक्री से अपील में विशेष अनुमति द्वारा अपील, एस. जे. शीर्षक अपील संख्या 1946 में प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय के निर्णय और डिक्री से उत्पन्न होती है, जो 1944 के शीर्षक सूट संख्या 34 में मोंघिर में अधीनस्थ न्यायाधीश के

प्रथम न्यायालय के 27 नवंबर, 1945 के निर्णय और डिक्री से उत्पन्न होती है।

एस. सी. इसाक्स (गणेश्वर प्रसाद और आर. सी. प्रसाद, उनके साथ) अपीलार्थियों के लिए।

बी. के. सरन और एम. एम. सिन्हा उत्तरदाता संख्या 1-9 के लिए।

14 अप्रैल 1954। न्यायालय का निर्णय वेंकटरामा अय्यर जे. द्वारा दिया गया

यह अपील वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 के निर्माण पर सवाल उठाता है। अपीलकर्ताओं ने वह मुकदमा दायर किया जिसमें से उनकी अपील, अधीन न्यायाधीश, मोंघिर के न्यायालय में, मौज़ा बर्डीह में स्थित 12 एकड़ 51 सेंट भूमि के कब्जे की वसूली के लिए उत्पन्न होती है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 12 और 13, दूसरे पक्ष का गठन करते हुए, मालिक हैं। शिकायत में आरोप हैं कि 12 अप्रैल, 1943 को वादी को दूसरे पक्ष द्वारा सलामी के रूप में 1950 रुपये की राशि के भुगतान पर अधिभोग किरायेदारों के रूप में स्वीकार किया गया था और भूमि पर कब्जा कर लिया गया, और इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 1 से 11 वाले पहले पक्ष ने उन पर अतिक्रमण किया और फसलों को ले गए। तदनुसार

प्रतिवादी संख्या 1 से 11 को अपने अतीत और भविष्य के लाभ के लिए निष्कासित करने के लिए मुकदमा दायर किया गया था और इसका मूल्य रु 2,950 रुपये बना। 1,950 कब्जे के लिए राहत का मूल्य है और रु 1,000 पिछले लाभ होने का दावा किया गया है।

प्रतिवादी संख्या 1 से 11 ने मुकदमा लड़ा। उन्होंने दलील दी कि वे फसली 1336 से बटाई प्रणाली पर किरायेदारों के रूप में भूमि के कब्जे में थे, और मकान मालिक के साथ उपज साझा कर रहे थे, और घरों में अधिभोग के अधिकार प्राप्त कर लिए थे, कि दूसरे पक्ष को उन्हें वादी पर निपटाने का कोई अधिकार नहीं था, और बाद वाले ने 12 अप्रैल, 1943 के समझौते के तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया था। प्रतिवादी संख्या 12 और 13 एकतरफा रहे।

अधीनस्थ न्यायाधीश ने दूसरे पक्ष की पटवारियों की लिखावट में ए से ए-114 के रूप में चिह्नित कुछ प्राप्तियों पर भरोसा करते हुए, जो फसली 1336 से 1347 तक की अवधि में थीं, यह निर्णय दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 11 तक 12 वर्षों से अधिक समय से खेती करने वाले किरायेदारों के रूप में कब्जे में थे और उन्होंने अधिभोग अधिकार प्राप्त किए थे, और 12 अप्रैल, 1943 के समझौते में वादी को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। तदनुसार उन्होंने मुकदमा खारिज कर

दिया। वादियों ने इस निर्णय के खिलाफ जिला न्यायाधीश, मोंघिर के न्यायालय में एक अपील को प्राथमिकता दी, जो परीक्षण न्यायालय से सहमत थे कि रसीदें, ए से ए-114 तक वास्तविक थीं, और कि प्रतिवादियों संख्या 1 से 11 ने अधिभोग अधिकार प्राप्त कर लिए थे, और तदनुसार अपील को खारिज कर दिया।

वादियों ने इस मामले को उच्च न्यायालय, पटना, 1946 की एस. ए. संख्या 1152 में दूसरी अपील में उठाया और वहां, पहली बार, स्टाम्प रिपोर्टर द्वारा वाद में मूल्यांकन पर आपत्ति जताई गई और जांच के बाद, न्यायालय ने निर्धारित किया कि मुकदमे का सही मूल्यांकन रु 9,980 है वादियों ने उनसे अपेक्षित अतिरिक्त न्यायालय-शुल्क का भुगतान किया, और फिर यह तर्क उठाया कि संशोधित मूल्यांकन पर, अधीनस्थ न्यायाधीश की डिक्री से अपील जिला न्यायालय में नहीं बल्कि उच्च न्यायालय में होगी, और तदनुसार 1946 की धारा 1152 को जिला न्यायालय के फैसले की अनदेखी करते हुए पहली अपील के रूप में सुना जाना चाहिए। विद्वान न्यायाधीशों ने रामदेव सिंह बनाम राज नारायण (1) मामले में उस न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय के बाद यह अभिनिर्धारित किया कि जिला न्यायालय में अपील सक्षम है, और इसके निर्णय को केवल तभी वापस लिया जा सकता है जब अपीलार्थी गुण-दोष पर पूर्वाग्रह स्थापित कर सकें, और यह अभिनिर्धारित करते हुए कि

साक्ष्य पर विचार करने पर ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं दिखाया गया था, उन्होंने दूसरी अपील को खारिज कर दिया। मामला अब विशेष अनुमति पर हमारे सामने आता है।

यह ध्यान दिया जाएगा कि वर्तमान कार्रवाई का परीक्षण करने के लिए उचित न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय, मोंघिर होगा, चाहे मुकदमे का मूल्यांकन शिकायत में दिए गए 2,950 रुपये हैं या 9,880 जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है; लेकिन यह उस मंच में एक अंतर लाएगा जिस पर उसके निर्णय से अपील होगी, चाहे एक मूल्यांकन या दूसरे को निर्णायक कारक के रूप में स्वीकार किया जाना है। वाद मूल्यांकन पर, अपील जिला न्यायालय में होगी; उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन पर, यह वह न्यायालय है जो अपील पर विचार करने के लिए सक्षम होगा। अपीलार्थियों का तर्क है कि मुकदमे के मूल्यांकन पर, जैसा कि अंततः निर्धारित किया गया है, जिला न्यायालय अपील को स्वीकार करने के लिए सक्षम नहीं था, उस न्यायालय द्वारा पारित डिक्री और निर्णय को शून्य के रूप में माना जाना चाहिए, कि उच्च न्यायालय को तदनुसार एस. ए. नं. 1946 का 1152 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत अपनी सीमाओं के साथ दूसरी अपील के रूप में नहीं, बल्कि अधीनस्थ न्यायाधीश, मोंघिर के फैसले और डिक्री के खिलाफ पहली अपील के रूप में और यह कि अपीलार्थी

पूर्ण सुनवाई के साथ-साथ कानून के तथ्य के प्रश्नों पर भी हकदार थे। और वैकल्पिक रूप से, यह तर्क दिया जाता है कि भले ही अपील पर जिला न्यायालय की डिक्री और निर्णय को शून्य के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और मामले को वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 के तहत निपटाया जाना है, अपीलार्थियों को उस धारा के अर्थ के भीतर "पूर्वाग्रह" का सामना करना पड़ा था, क्योंकि अधीनस्थ न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ उनकी अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा नहीं बल्कि निम्न अधिकार क्षेत्र के न्यायालय, अर्थात मोंघिर के जिला न्यायालय द्वारा की गई थी, और इसलिए इसकी डिक्री को दरकिनार किया जाना चाहिए था, और उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष में सुनी गई अपील को पहली अपील के रूप में।

(I) आई एल आर 27 पटना 109, एआईआर 1949 पटना 27 बी

इन दलीलों का जवाब इस बात पर निर्भर करना चाहिए कि कानूनी स्थिति क्या है जब कोई न्यायालय किसी मुकदमे या अपील पर विचार करता है, जिस पर उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, और उस स्थिति पर वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 का क्या प्रभाव पड़ता है। यह एक मौलिक सिद्धांत है जो अच्छी तरह से स्थापित है कि अधिकार क्षेत्र के बिना किसी न्यायालय द्वारा पारित एक डिक्री एक

अमान्यता है, और इसकी अयोग्यता को जब भी और जहां भी इसे लागू करने या उस पर भरोसा करने की मांग की जाती है, यहां तक कि निष्पादन के चरण में और यहां तक कि संपार्श्विक कार्यवाही में भी स्थापित किया जा सकता है। अधिकारिता का एक दोष, चाहे वह आर्थिक हो या क्षेत्रीय, या चाहे वह कार्रवाई के विषय के संबंध में हो, किसी भी डिक्री को पारित करने के लिए न्यायालय के अधिकार पर हमला करता है, और इस तरह के दोष को पक्षों की सहमति से भी ठीक नहीं किया जा सकता है। यदि अब विचाराधीन प्रश्न का निर्धारण केवल मामले को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर किया जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि मोंघिर का जिला न्यायालय गैर-न्यायिक था, और इसका निर्णय और डिक्री अमान्य होगी। सवाल यह है कि इस स्थिति पर वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 का क्या प्रभाव पड़ता है।

धारा 11 यह अधिनियमित करती है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 578 में कुछ भी होने के बावजूद, एक आपत्ति कि एक न्यायालय जिसका किसी मुकदमे या अपील पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, ने अति-मूल्यांकन या कम-मूल्यांकन के कारण इसका प्रयोग किया था, एक अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि धारा में प्रावधान किया गया है। फिर इन प्रावधानों का पालन करें

कि आपत्तियों पर कब विचार किया जा सकता है और उनसे कैसे निपटा जाए। खंड का मसौदा तैयार किया गया है और काफी आलोचना के लिए योग्य है; लेकिन बहुत कुछ अस्पष्ट और भ्रमित होने के बीच, एक सिद्धांत है जो स्पष्ट और विशिष्ट है। यह है कि किसी न्यायालय द्वारा पारित डिक्री, जिसे किसी वाद या अपील की सुनवाई करने की कोई अधिकारिता नहीं थी, लेकिन अति-मूल्यांकन या अल्प-मूल्यांकन के लिए, इसे इस धारा के लिए शून्य और शून्य के रूप में माना जाना चाहिए, और यह कि अति-मूल्यांकन या अल्प-मूल्यांकन के आधार पर अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति को उस धारा के तहत निपटाया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। धारा के प्रारंभिक शब्दों में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 578, अब धारा 99 का संदर्भ महत्वपूर्ण है। वह धारा, यह उपबंध करते हुए कि किसी भी डिक्री को उसमें उल्लिखित दोषों के कारण अपील में उलट या परिवर्तित नहीं किया जाएगा, जब वे मामले के गुण-दोषों को प्रभावित नहीं करते हैं, सिवाय इसके कि इसकी अधिकारिता के संचालन दोषों के। इसलिए धारा 99 गुण-दोष पर पारित फरमानों को कोई संरक्षण नहीं देती है, जब उन्हें पारित करने वाले न्यायालयों के पास अति-मूल्यांकन या अवमूल्यन के परिणामस्वरूप अधिकार क्षेत्र का अभाव था। इस परिणाम से बचने के लिए धारा 11 अधिनियमित की गई थी। इसमें यह प्रावधान है कि अति-मूल्यांकन या अल्प-मूल्यांकन के आधार

पर किसी न्यायालय की अधिकारिता पर आपत्तियों को किसी अपीलीय न्यायालय द्वारा धारा में उल्लिखित तरीके और सीमा के अलावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह अपने आप में एक पूर्ण स्व-निहित प्रावधान है, और अति-मूल्यांकन या कम-मूल्यांकन पर पारित अधिकार क्षेत्र पर इसके अनुसार के अलावा कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है। क्षेत्रीय अधिकारिता से संबंधित आपत्तियों के संदर्भ में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 यह अधिनियमित करती है कि अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा मुकदमा करने के स्थान पर किसी भी आपत्ति की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि न्याय की परिणामी विफलता न हो, यह वही सिद्धांत है जिसे मुकदमा मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 में आर्थिक अधिकारिता के संदर्भ में अपनाया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 और 99 और वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 में अंतर्निहित नीति एक ही है, अर्थात्, जब किसी मामले की सुनवाई किसी न्यायालय द्वारा गुण-दोष और दिए गए निर्णय के आधार पर की गई थी, तो इसे विशुद्ध रूप से तकनीकी आधार पर उलटने के लिए उत्तरदायी नहीं होना चाहिए, जब तक कि यह न्याय की विफलता का कारण न बना हो, और विधानमंडल की नीति क्षेत्रीय और आर्थिक दोनों क्षेत्राधिकार की आपत्तियों को तकनीकी के रूप में मानने के लिए रही है और अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार के लिए

स्वतंत्र नहीं है, जब तक कि गुण-दोष पर कोई पूर्वाग्रह न हो। इसलिए, अपीलार्थियों का यह तर्क कि जिला न्यायालय, मोंघिर की डिक्री और निर्णय को अमान्य माना जाना चाहिए, वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 के तहत कायम नहीं किया जा सकता है।

अपीलार्थी राजलक्ष्मी दासी बनाम कात्यायनी दासी और सिदप्पा वेंकटराव बनाम रचप्पा सुबराव की ओर से, जिसे रचप्पा सुबराव जाधव बनाम सिदप्पा वेंकटराव जाधव में प्रिवी काउंसिल द्वारा पुष्टि की गई थी, इस तर्क का समर्थन करने के लिए भरोसा किया गया था कि यदि अपील न्यायालय को अपील पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होता, यदि मुकदमे का सही मूल्यांकन किया गया होता, तो उसके द्वारा पारित डिक्री को शून्य माना जाना चाहिए। राजलक्ष्मी दासी बनाम कात्यायनी दासी में, तथ्य यह थे कि एक कात्यायनी दासी ने अपने पति जोगेंद्र की संपत्ति की वसूली के लिए अधीनस्थ न्यायाधीश, अलीपुर के न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें दावे का मूल्य रु 2,100 जबकि संपत्ति की कीमत एक लाख रुपये से अधिक थी। मुकदमे का फैसला सुनाया गया, और प्रतिवादियों ने जिला न्यायालय में अपील को प्राथमिकता दी, जो वाद मूल्यांकन पर अपील पर विचार करने के लिए उचित न्यायालय था। वहाँ, पक्षों ने मामले से समझौता किया, और एक सहमति आदेश पारित किया गया, जिसमें प्रतिवादियों के स्वामित्व

को संपत्ति के कुछ हिस्सों में मान्यता दी गई। फिर, जोगेंद्र की बेटी, राजलक्ष्मी दासी ने एक घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया कि जिस सहमति आदेश में उनकी मां एक पक्ष थी, वह वापसी करने वालों पर बाध्यकारी नहीं था। उनके द्वारा आग्रह किए गए आधारों में से एक यह था कि कात्यायनी के मुकदमे को जानबूझकर कम महत्व दिया गया था, कि यदि इसे सही ढंग से महत्व दिया गया होता, तो यह उच्च न्यायालय होता जिसके पास अपील को स्वीकार करने की क्षमता होती, और यह कि जिला न्यायाधीश द्वारा पारित सहमति डिक्री तदनुसार एक शून्य थी। इस तर्क से सहमत होते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि एक न्यायालय द्वारा पारित एक डिक्री, जिसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, एक अमान्यता थी, और यह कि पक्षों की सहमति भी दोष को ठीक नहीं कर सकती थी। उस मामले में, सवाल एक ऐसे व्यक्ति द्वारा उठाया गया था जो कार्रवाई और संपार्श्विक कार्यवाही में पक्षकार नहीं था, और अदालत ने माना: "अब हमें इस बात पर विचार करने के लिए नहीं कहा गया है कि जहां तक पक्षकारों का संबंध है, इस तरह की अधिकारिता की कमी का डिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह स्पष्ट है कि जहां तक डिक्री के लिए एक अजनबी का संबंध है, जो डिक्री से प्रभावित संपत्ति में रुचि रखता है, वह स्पष्ट रूप से एक घोषणा के लिए कह

सकता है कि डिक्री एक शून्य है, क्योंकि एक अदालत द्वारा बनाई गई थी जिसका मुकदमे के विषय-वस्तु पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।"

तथ्यों पर, वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 के प्रभाव का प्रश्न निर्धारण के लिए उत्पन्न नहीं हुआ था और उस पर विचार नहीं किया गया था।

सिदप्पा वेंकटराव बनाम रचप्पा सुबराव में वादी ने अधीनस्थ न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी के न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें यह घोषणा की गई कि वह एक वेंकटराव का गोद लिया हुआ पुत्र है और प्रतिवादी को उसके घर के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए एक निषेधाज्ञा के लिए। शिकायत में घोषणा का मूल्य रु 130 और निषेधाज्ञा के लिए 5 रुपये, और मुक़दमे का मूल्य प्लीडर के शुल्क के उद्देश्यों के लिए रु 69,016-9-0 संपत्ति का मूल्य है। मुकदमा अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा तय किया गया था, और उसकी डिक्री के खिलाफ प्रतिवादी ने जिला न्यायालय में अपील की, जिसने अपील की अनुमति दी और मुकदमे को खारिज कर दिया। वादी ने उच्च न्यायालय में दूसरी अपील में मामले को उठाया, और तर्क दिया कि वाद में मूल्यांकन पर अधीनस्थ न्यायाधीश की डिक्री के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में है, और जिला न्यायालय में अपील अक्षम थी। इस तर्क को

बरकरार रखा गया और जिला न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार कर दिया गया। यह देखा जाएगा कि विवाद का मुद्दा यह था कि क्या वाद में लगाए गए आरोपों पर अधिकार क्षेत्र के उद्देश्यों के लिए मूल्य रु 135 या रु 69,016-9-0 था, और निर्णय यह था कि यह बाद वाला था। अति-मूल्यांकन या कम-मूल्यांकन का कोई सवाल ही नहीं उठा और वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 के दायरे पर कोई निर्णय नहीं दिया गया।

अपने निर्णय के परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय पहली अपील के रूप में मामले पर विचार करने आया और अधीनस्थ न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की। इसके बाद प्रतिवादी ने रचप्पा सुब्राव जाधव बनाम सिदप्पा वेंकटराव जाधव मामले में प्रिवी काउंसिल में अपील करने के लिए मामला उठाया और वहां उनका तर्क था कि वास्तव में, इसके सही मूल्यांकन पर मुकदमे की सुनवाई द्वितीय श्रेणी के अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा की जा सकती थी, और यह कि जिला न्यायालय अपील पर विचार करने के लिए उचित न्यायालय था। प्रिवी काउंसिल ने अभिनिर्धारित किया कि यह आपत्ति जो "तकनीकी रूप से सबसे अधिक तकनीकी" थी, पहली बार के न्यायालय में नहीं ली गई थी, और यह कि न्यायालय उस प्रकार की आपत्ति की सहायता करने में उचित नहीं होगा और यह भी असमर्थनीय था। समापन से पहले, यह देखा गया।

"न्यायालय शुल्क अधिनियम एक वादी को अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ तकनीकी हथियार से लैस करने के लिए नहीं बल्कि राज्य के लाभ के लिए राजस्व प्राप्त करने के लिए पारित किया गया था। इस वाद में प्रतिवादी अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग राज्य के हितों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि वादी को बाधित करने के लिए करना चाहता है; वह यह तर्क नहीं देता है कि न्यायालय ने गलत तरीके से राजस्व को नुकसान पहुंचाने का निर्णय लिया, लेकिन यह कि उसने मामले को अधिकार क्षेत्र के बिना निपटाया। इन परिस्थितियों में यह याचिका, जिला न्यायालय में अपील की सुनवाई में पहली बार आगे बढ़ाई गई, गलत धारणा है, और उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से खारिज कर दी गई थी।

अपीलार्थियों के इस तर्क का समर्थन करना कि मोंघिर के जिला न्यायालय द्वारा अपील में पारित डिक्री को अमान्य माना जाना चाहिए, इन टिप्पणियों से पता चलता है कि अब जिस प्रकार की आपत्ति को अत्यधिक तकनीकी होने के कारण सामने रखा गया है, उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए यदि पहली बार अदालत में नहीं उठाया गया हो। इसलिए हमारी राय है कि जिला न्यायालय, मोंघिर के आदेश और निर्णय को अमान्य नहीं माना जा सकता है।

इसके बाद यह तर्क दिया जाता है कि मामले को वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 द्वारा शासित मानते हुए भी, अपीलार्थियों के प्रति पूर्वाग्रह था, जिसमें कम मूल्यांकन के कारण, उनकी अपील की सुनवाई निम्न अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा की गई थी, जबकि वे तथ्यों पर उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के हकदार थे। यह तर्क दिया गया था कि अपील का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार था, और इसलिए तथ्यों पर उच्च न्यायालय में अपील करने के अपीलार्थियों के अधिकार से वंचित होने को पूर्वाग्रह के रूप में माना जाना चाहिए। यह तर्क एक गलत धारणा पर आगे बढ़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपील का अधिकार एक मूल अधिकार है और इससे वंचित होना एक गंभीर पूर्वाग्रह है; लेकिन अपीलकर्ताओं को अधीनस्थ न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील करने के अधिकार से वंचित नहीं किया गया है। कानून उस फैसले के खिलाफ जिला न्यायालय में अपील प्रदान करता है, और वादी ने उस अधिकार का प्रयोग किया है। वास्तव में, अवमूल्यन ने अपीलार्थी के अपील करने के अधिकार को बढ़ा दिया है, क्योंकि हालाँकि उन्हें केवल एक अपील का अधिकार होता और उच्च न्यायालय का अधिकार होता, यदि वाद को सही ढंग से महत्व दिया गया होता, तो कम मूल्यांकन के कारण उन्होंने दो अपीलों का अधिकार प्राप्त किया, एक जिला न्यायालय में और दूसरी उच्च न्यायालय में। अपीलार्थियों की

शिकायत वास्तव में यह नहीं है कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील करने के अधिकार से वंचित किया गया था, जो वे नहीं कर चुके हैं, बल्कि यह है कि उस फैसले के खिलाफ तथ्यों पर अपील की सुनवाई जिला न्यायालय द्वारा की गई थी न कि उच्च न्यायालय द्वारा। अतः यह आपत्ति इस बात के बराबर है कि अपील के मंच में परिवर्तन अपने आप में वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 के उद्देश्य के लिए पूर्वाग्रह का विषय है।

इसलिए, सवाल यह है कि क्या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा अपील पर पारित डिक्री, जिसे केवल कम मूल्यांकन के कारण इसे स्वीकार करने का अधिकार था, को इस आधार पर दरकिनार किया जा सकता है कि सही मूल्यांकन पर कि न्यायालय अपील को स्वीकार करने के लिए सक्षम नहीं था? तीन उच्च न्यायालयों ने पूर्ण पीठों में इस मामले पर विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि केवल मंच का परिवर्तन वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 के अर्थ के भीतर पूर्वाग्रह नहीं है। वीडियो केलु अच्चन बनाम चेरिया पार्वती नेथियार, मूलचंद बनाम राम किशन और रामदेव सिंह बनाम राय नारायण। हमारे निर्णय में, इन निर्णयों में व्यक्त राय सही है। वास्तव में, खंड की भाषा में एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचना असंभव है। यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय द्वारा किसी अपील की सुनवाई का तथ्य,

जिसमें अपील उच्च न्यायालय में होती, यदि सही मूल्यांकन दिया गया होता, स्वयं पूर्वाग्रह का विषय है, तो अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय द्वारा पारित डिक्री, अधिक के बिना, रद्द करने के लिए उत्तरदायी होनी चाहिए, और शब्द "जब तक कि इसके अति-मूल्यांकन या कम-मूल्यांकन ने मुकदमे के निपटान या उसके गुण-दोष पर अपील को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया है" पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। ये शब्द स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि ऐसे मामलों में पारित फरमान एक अपीलीय न्यायालय में हस्तक्षेप करने के लिए उत्तरदायी हैं, सभी मामलों में और निश्चित रूप से एक मामले के रूप में नहीं, बल्कि केवल तभी जब पूर्वाग्रह जैसा कि धारा के परिणामों में उल्लेख किया गया है। और इसलिए उस धारा द्वारा परिकल्पित पूर्वाग्रह एक अलग मंच पर सुनवाई की जा रही अपील के अलावा कुछ और होना चाहिए। एक विपरीत निष्कर्ष इस आश्चर्यजनक परिणाम की ओर ले जाएगा कि धारा को अति-मूल्यांकन या कम-मूल्यांकन के कारण उत्पन्न होने वाले अधिकार क्षेत्र के दोषों को ठीक करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था, लेकिन वास्तव में, इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया गया है। इसलिए हमारी स्पष्ट राय है कि इस धारा द्वारा विचार किया गया पूर्वाग्रह उस अपील की सुनवाई के तथ्य से कुछ अलग है जिसकी सुनवाई एक

ऐसे मंच में की गई थी जो अंततः निर्धारित किए गए मुकदमे के सही मूल्यांकन पर इसे सुनने के लिए सक्षम नहीं होता।

इसके बाद यह तर्क दिया जाता है कि इस दृष्टिकोण से कि निचले अपीलीय न्यायालय की डिक्री को केवल गुण-दोष पर पूर्वाग्रह के प्रमाण पर उलट दिया जा सकता है, दूसरे अपीलीय न्यायालय को यह पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या पूर्वाग्रह था, तथ्यों पर अपील को पूरी तरह से सुनना चाहिए और वास्तव में, इसे पहली अपील के रूप में सुना जाना चाहिए। रामदेव सिंह बनाम राज नारायण में दो विद्वान न्यायाधीशों की टिप्पणियों पर रिलायंस को इस तर्क के समर्थन में रखा गया है। वहाँ, न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा कि हालाँकि दूसरी अपील को पहली अपील के रूप में नहीं माना जा सकता है, लेकिन तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर निर्णय के गुण-दोष में जाकर पूर्वाग्रह स्थापित किया जा सकता है, और यह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 103 के तहत किया जा सकता है। मेरेडिथ जे. ने सहमति व्यक्त की कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पूर्वाग्रह था या नहीं, तथ्य के प्रश्नों पर निर्णयों के गुण-दोष की जांच होनी चाहिए; लेकिन उनकी राय थी कि यह मुकदमा मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 के तहत ही किया जा सकता है। तथापि, जे. दास ने इस मुद्दे पर कोई राय व्यक्त करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह उस स्तर पर उत्पन्न नहीं हुआ था। अपीलार्थियों की

शिकायत यह है कि दूसरी अपील की सुनवाई करने वाले विद्वान न्यायाधीशों ने, हालांकि वे रामदेव सिंह बनाम राज नारायण में निर्णय का पालन करने के लिए इच्छुक थे, वास्तव में ऐसा नहीं किया, और यह कि तथ्य के उन प्रश्नों से संबंधित साक्ष्य पर कोई विचार नहीं किया गया था जिन पर पक्षकार विवाद में थे।

यह हमें इस सवाल पर लाता है कि वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 में "पूर्वाग्रह" का क्या अर्थ है। क्या इसमें पक्षों के बीच तथ्य के मुद्दों पर निष्कर्षों में त्रुटियां शामिल हैं? यदि ऐसा होता है, तो दूसरी अपील की सुनवाई करने वाले न्यायालय के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह साक्ष्य की पूरी तरह से जांच करे और यह तय करे कि निचली अपीलीय अदालत द्वारा लिए गए निष्कर्ष सही हैं या नहीं। यदि यह उन निष्कर्षों से सहमत है, तो यह निर्णय की पुष्टि करेगा; यदि यह नहीं करता है, तो यह इसे उलट देगा। इसका मतलब है कि दूसरी अपील का न्यायालय वस्तुतः पहली अपील के न्यायालय की स्थिति में है। वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 की भाषा स्पष्ट रूप से इस तरह के दृष्टिकोण के खिलाफ है। यह प्रावधान करता है कि अति-मूल्यांकन या कम-मूल्यांकन ने गुण-दोष के आधार पर मामले के निपटान को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया होगा। गुणों पर पूर्वाग्रह सीधे तौर पर अति-मूल्यांकन या कम-मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और

साक्ष्य पर विचार करने पर तथ्य के निष्कर्ष में त्रुटि को संभवतः अति-मूल्यांकन या कम-मूल्यांकन के कारण नहीं कहा जा सकता है; इसलिए निर्धारण के लिए बिंदुओं पर निष्कर्षों में केवल त्रुटियों को धारा की भाषा द्वारा स्पष्ट रूप से रोक दिया जाएगा। यह आगे ध्यान दिया जाना चाहिए कि सिविल प्रक्रिया संहिता में कोई प्रावधान नहीं है, जो दूसरी अपील के न्यायालय को उन तथ्यों के प्रश्नों में जाने के लिए अधिकृत करता है जिन पर निचली अपीलीय अदालत ने निष्कर्ष दर्ज किए हैं और उन्हें उलटने के लिए। रामदेव सिंह बनाम राज नारायण में ऐसी शक्ति प्रदान करने के लिए धारा 103 पर भरोसा किया गया था। लेकिन वह धारा केवल तभी लागू होती है जब निचली अपीलीय अदालत किसी भी मुद्दे पर निष्कर्ष दर्ज करने में विफल रही हो, या जब सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत आने वाली अनियमितताएं या दोष थे। यदि ये शर्तें मौजूद हैं, तो अपील के तहत निर्णय वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 का सहारा लिए बिना दूसरी अपील के न्यायालय की सामान्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए अलग किया जा सकता है। यदि वे मौजूद नहीं हैं, तो सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कोई अन्य शक्ति नहीं है जो दूसरी अपील के न्यायालय को तथ्य के निष्कर्षों को दरकिनार करने और उन प्रश्नों पर अपील की फिर से सुनवाई करने के लिए अधिकृत करती है। हमें तदनुसार यह अभिनिर्धारित करना चाहिए कि एक अपीलीय

न्यायालय को वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 के तहत इस बात पर विचार करने की कोई शक्ति नहीं है कि क्या निचली अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष सही हैं, और उन निष्कर्षों में त्रुटि को उस धारा के अर्थ के भीतर पूर्वाग्रह नहीं माना जा सकता है।

अब तक, "पूर्वाग्रह" की परिभाषा नकारात्मक रही है-कि यह केवल मंच का परिवर्तन या गुण-दोष पर निर्णय में केवल त्रुटि नहीं हो सकती है। फिर धारा 11 के उद्देश्य के लिए सकारात्मक पूर्वाग्रह क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने धारा के अधिनियमन के बाद से भारत में न्यायालयों को उत्तेजित किया है। यह सुझाव दिया गया है कि यदि वाद या अपील की उचित सुनवाई नहीं हुई थी और जिसके परिणामस्वरूप अन्याय हुआ था, तो यह वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 के तहत पूर्वाग्रह होगा। पूर्वाग्रह का एक अन्य उदाहरण तब होता है जब एक मुकदमा जिसे मूल मुकदमे के रूप में दायर किया जाना चाहिए था, छोटे कारण पक्ष पर कम मूल्यांकन के परिणामस्वरूप दायर किया जाता है। लघु कारण न्यायालय में मुकदमों के मुकदमे की प्रक्रिया संक्षिप्त है; खोज या निरीक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं; साक्ष्य को विस्तार से दर्ज नहीं किया जाता है, और इसके निर्णय के खिलाफ अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी एक विस्तृत प्रक्रिया और

अपील के अधिकार का लाभ खो देता है जो उसके पास होता, अगर मुकदमा मूल पक्ष पर दायर किया गया होता। ऐसे मामले में यह कहा जा सकता है कि लघु कारणों के न्यायालय द्वारा मुकदमे के निपटारे ने मामले के गुण-दोष को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। हालाँकि, वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 के तहत आने वाले पूर्वाग्रह के सभी संभावित मामलों को पूरी तरह से सूचीबद्ध करने का प्रयास करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है। उस धारा के तहत अपीलीय न्यायालयों को जो अधिकारिता प्रदान की जाती है, उसका प्रयोग न्यायसंगत होता है, जब किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अति-मूल्यांकन या अवमूल्यन और न्याय की परिणामी विफलता के परिणामस्वरूप अधिकारिता की गलत धारणा की गई हो। इस तरह के अधिकार क्षेत्र को बारीकी से परिभाषित करना या इसे निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर सीमित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है। इसके बारे में केवल यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि जब भी तथ्य और परिस्थितियां इसकी मांग करती हैं कि पूर्वाग्रह हुआ है या नहीं, तो इसका उपयोग सावधानी के साथ और न्याय के उद्देश्यों के लिए एक पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र की प्रकृति में किया जाना चाहिए, तदनुसार, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्धारित किया जाने वाला मामला है।

अब हमें यह देखना होगा कि क्या कम मूल्यांकन के कारण अपीलार्थियों को कोई पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा है। वे कार्रवाई में वादी थे। उन्होंने सूट का मूल्य रु 2, 950 निर्धारित किया। प्रतिवादियों ने किसी भी समय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर कोई आपत्ति नहीं जताई। जब वादी एक विस्तृत ट्रायल के बाद मुकदमा हार जाते हैं, तो वे ही होते हैं जिन्होंने अपने मूल्यांकन पर जिला न्यायालय में अपील की, जैसा कि वे बाध्य थे। वहाँ भी, प्रतिवादियों ने अपील की सुनवाई के लिए जिला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर कोई आपत्ति नहीं जताई। जब निर्णय वादी के खिलाफ गुण-दोष पर चला गया, तो उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में 1946 की धारा ए. संख्या 1152 को प्राथमिकता दी, और यदि स्टाम्प रिपोर्टर ने मूल्यांकन और अदालत द्वारा भुगतान किए गए शुल्क पर आपत्ति नहीं उठाई होती, तो वादी अपील की सुनवाई के लिए जिला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को चुनौती नहीं देते। यह कानून की एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी, यदि वादी जिन्होंने अपनी पसंद के न्यायालय में कार्यवाही शुरू की थी, वे बाद में पलट सकते हैं और मूल्यांकन में त्रुटि के आधार पर इसके अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठा सकते हैं जो उनकी अपनी थी। यदि कानून यह होता कि किसी न्यायालय की डिक्री, जिसका वाद या अपील पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होता, लेकिन अति-मूल्यांकन या अवमूल्यन के लिए, एक शून्य के रूप

में माना जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से, उन्हें इस तथ्य से न्यायालय में अधिकार क्षेत्र की कमी स्थापित करने से नहीं रोका जाएगा कि उन्होंने खुद इसे लागू किया था। हालाँकि, यह मुकदमा मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 के तहत स्थिति नहीं है। फिर वादी को अपने द्वारा उठाए गए पद से अपने विरोधियों के पूर्वाग्रह के लिए पीछे हटने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए, जिन्होंने उसमें सहमति व्यक्त की थी?

भारतीय न्यायालयों में यह पर्याप्त अधिकार है कि "या" शब्द के उपयोग के बावजूद, वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 के खंड (ए) और (बी) को संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए। यदि यह सही व्याख्या है, तो वादी को अपीलीय न्यायालय में अधिकार क्षेत्र के बारे में आपत्ति उठाने से रोक दिया जाएगा। लेकिन भले ही दोनों प्रावधानों का अलग-अलग अर्थ लगाया जाना है, और धारा 11 (1) (बी) के तहत पक्षकारों को अपीलीय न्यायालय में पहली बार आपत्ति उठाने का अधिकार है, फिर भी, पूर्वाग्रह की आवश्यकता को पूरा करना होगा, और जिस पक्ष ने अपने स्वयं के मूल्यांकन पर अपनी पसंद के मंच का सहारा लिया है, उसे स्वयं किसी भी पूर्वाग्रह की शिकायत करने के लिए नहीं सुना जा सकता है। पूर्वाग्रह केवल तभी राहत का आधार हो सकता है जब यह दूसरे पक्ष की कार्रवाई के कारण हो, न कि जब यह अपने स्वयं के कार्य

के परिणामस्वरूप हो। अदालतें इसे पूर्वाग्रह के रूप में मान्यता नहीं दे सकती हैं जो उसी पक्ष की कार्रवाई से बहती है जो इसके बारे में शिकायत करता है। इसके अलावा भी, हम संतुष्ट हैं कि जिला न्यायालय द्वारा उनकी अपील की सुनवाई किए जाने से अपीलार्थियों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं पैदा हुआ। उस न्यायालय द्वारा अपील की निष्पक्ष और पूर्ण सुनवाई हुई; इसने मामले में पूरे साक्ष्य पर विचार करने के गुण-दोष पर अपना निर्णय दिया, और किसी भी अन्याय के परिणामस्वरूप मामले का निपटारा नहीं किया गया। विद्वान न्यायाधीशों का यह निर्णय कि वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 के तहत हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं था, सही है। नतीजतन, अपील विफल हो जाती है और लागत के साथ खारिज की जाती है।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।